



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08092022-238666
CG-DL-E-08092022-238666

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 211]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 7, 2022/भाद्र 16, 1944

No. 211]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 7, 2022/BHADRA 16, 1944

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 सितम्बर, 2022

अंतिम जांच परिणाम

मामला सं. एडी (एनएसआर) -01/2021

विषय: बंगलादेश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “हाइड्रोजन पैरोऑक्साइड” के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क से संबंधित यथा-संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 22 के अंतर्गत मैसर्स अल-राजी केमिकल कांप्लेक्स लिमिटेड, बंगलादेश (उत्पादक/निर्यातक) के अनुरोध के अनुसार 10.9.2021 को शुरु की गई न्यू शिपर समीक्षा।

सं. 7/25/2021-डीजीटीआर.—समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (इसके बाद इसे “अधिनियम” भी कहा गया है) और समय समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे “नियमावली” भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए:

क. मामले की पृष्ठभूमि

2. निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे “प्राधिकारी” भी कहा गया है) द्वारा बंगलादेश, ताइवान, कोरिया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान और थाइलैंड (जिन्हें आगे “संबद्ध देश” भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित हाइड्रोजन पैरोऑक्साइड (जिसे आगे “संबद्ध वस्तु” या “विचाराधीन उत्पाद” भी कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटन की प्रकृति और मात्रा तथा घरेलू उद्योग पर इसके क्षतिकारी प्रभाव की जांच के लिए 14 जनवरी, 2016 को एक मूल पाटनरोधी जांच शुरू की गई थी। प्राधिकारी ने अपने अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना सं. 14/03/2015-डीजीएडी दिनांक 11 अप्रैल, 2017 द्वारा इंडोनेशिया को छोड़कर इन देशों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की थी जिसे केन्द्र सरकार (राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय) द्वारा 5 वर्षों की अवधि के लिए सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 28/2017-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 14 जून, 2017 के माध्यम से लगाया गया था।
3. उक्त अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना को माननीय सेस्टेट के समक्ष चुनौती दी गई थी। तत्पश्चात् माननीय सेस्टेट के आदेश सं. 58470-58474/2017 दिनांक 20 दिसंबर, 2017 के अनुपालन में प्राधिकारी द्वारा अधिसूचना सं. 14/03/2015-डीजीएडी दिनांक 17 अप्रैल, 2018 के माध्यम से संशोधित अंतिम जांच परिणाम अधिसूचित किए गए। संशोधित जांच परिणामों में प्राधिकारी ने क्षति रहित कीमत (एनआईपी) पुनःनिर्धारित की और संबद्ध देशों से हाइड्रोजन पैरोऑक्साइड के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की संशोधित राशि की सिफारिश की। प्राधिकारी द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा पांच वर्षों की अवधि के लिए अधिसूचना सं. 33/2018-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 1 जून, 2018 के माध्यम से निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था। इस प्रकार लगाया गया शुल्क यदि आगे बढ़ाया न जाए तो 13 जून, 2022 को समाप्त होना था।
4. मैसर्स अल-राजी केमिकल कॉम्प्लेक्स लिमिटेड, बंगलादेश (उत्पादक/निर्यातक) ने सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली के नियम 22 के अनुसार न्यू शिपर समीक्षा (एनएसआर) के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें बंगलादेश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “हाइड्रोजन पैरोऑक्साइड” के आयातों के संबंध में न्यू शिपर समीक्षा (एनएसआर) हेतु अनुरोध किया गया है तथा मैसर्स अल-राजी केमिकल कॉम्प्लेक्स लिमिटेड द्वारा किए गए हाइड्रोजन पैरोऑक्साइड के निर्यातों के संबंध में उसके लिए अलग पाटन मार्जिन का दावा किया गया है।
5. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 22 के अंतर्गत निर्धारित शर्तों से प्रथमदृष्टया संतुष्ट होते हुए मैसर्स अल-राजी केमिकल कॉम्प्लेक्स लिमिटेड, बंगलादेश (उत्पादक/निर्यातक) के संबंध में बंगलादेश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित हाइड्रोजन पैरोऑक्साइड के आयातों पर लागू किए जाने वाले पाटनरोधी शुल्क के प्रयोजनार्थ अलग पाटन मार्जिन के निर्धारण हेतु अधिसूचना सं. 7/25/2021-डीजीटीआर दिनांक 10 सितंबर, 2021 के माध्यम से एक न्यू शिपर समीक्षा जांच की शुरुआत की।
6. वित्त मंत्रालय ने अधिसूचना सं. 72/2021-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 17 दिसंबर, 2021 के माध्यम से पूर्वोक्त एनएसआर जांच के पूरा होने तक मैसर्स अल-राजी केमिकल कॉम्प्लेक्स लिमिटेड, बंगलादेश (उत्पादक/निर्यातक) द्वारा किए गए संबद्ध वस्तु के सभी निर्यातों का अनंतिम आकलन किया।
7. इस एनएसआर के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि (पीओआई) 1 अप्रैल, 2021 से 31 दिसंबर, 2021 तक निर्धारित की गई थी।
8. उक्त के होते हुए भी, बंगलादेश और थाइलैंड के मूल के अथवा वहां से निर्यातित हाइड्रोजन पैरोऑक्साइड पर लागू पाटनरोधी शुल्क की प्राधिकारी द्वारा घरेलू उद्योग द्वारा दायर आवेदन के आधार पर निर्णायक समीक्षा की गई थी और शुल्क जारी रखने के लिए अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना फा.सं. 7/22/2021-डीजीटीआर दिनांक 11 मार्च, 2022 के तहत अधिसूचित की गई थी। तथापि, वित्त मंत्रालय ने कार्यालय ज्ञापन सं. सीबीआईसी-190354/271/2021-टीओ (टीआरयू-1)-सीबीईसी दिनांक 22 जून, 2022 के माध्यम से यह सूचित किया कि केन्द्र सरकार ने निर्दिष्ट प्राधिकारी की सिफारिश पर विचार करने के बाद फा. सं. 7/22/2021-डीजीटीआर

दिनांक 11 मार्च, 2022 के माध्यम से अधिसूचित शुल्कों को जारी रखने की सिफारिश को स्वीकार नहीं करने का निर्णय लिया है। उक्त निर्णय के परिणामस्वरूप, बंगलादेश से संबद्ध वस्तु पर लागू शुल्क सहित संबद्ध वस्तुओं पर लागू पाटनरोधी शुल्क 13 जून, 2022 को समाप्त हो गया है।

ख. इस जांच में अपनाई गई प्रक्रिया

9. वर्तमान जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया अपनाई गई है:

- i. प्राधिकारी ने संबद्ध एनएसआर पाटनरोधी जांच की शुरुआत करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित अधिसूचना सं. 7/25-2021-डीजीटीआर दिनांक 10 सितंबर, 2021 के माध्यम से एक सार्वजनिक सूचना जारी की।
- ii. प्राधिकारी ने निर्यातक प्रश्नावली की एक प्रति के साथ आवेदक के लिए जांच शुरुआत अधिसूचना की एक प्रति भेजी थी और उससे लिखित में अपने विचारों से अवगत कराने का अवसर दिया और पीओआई समाप्त होने के बाद विहित प्रश्नावली में संगत आंकड़े प्रस्तुत करने का अवसर दिया।
- iii. प्राधिकारी ने जांच शुरुआत अधिसूचना की एक प्रति भारत में बंगलादेश के उच्चायोग को भी भेजी थी।
- iv. प्राधिकारी ने भारत में ज्ञात घरेलू उत्पादकों को जांच शुरुआत अधिसूचना की एक प्रति भेजी थी और लिखित में अपने विचारों से अवगत कराने का अवसर दिया था। आवेदन के अगोपनीय अंश की एक प्रति ई-मेल के जरिए हितबद्ध पक्षकारों को भी भेजी गई थी।
- v. जांच शुरुआत अधिसूचना के उत्तर में मैसर्स अल-राजी केमिकल कांप्लेक्स लिमिटेड, बंगलादेश (उत्पादक/निर्यातक) {एनएसआर आवेदक} द्वारा निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर दिया गया था। भारत में “हाइड्रोजन पैरोआक्साइड” के घरेलू उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाले नेशनल पैरोआक्साइड लिमिटेड और एक आयातक/प्रयोक्ता/व्यापारी अर्थात् संदीप आर्गेनिक्स लिमिटेड ने वर्तमान एनएसआर जांच में अपनी रुचि दिखाई है।
- vi. चूंकि कोविड महामारी के कारण वास्तविक आवागमन कम हो गया था, इसलिए सभी हितबद्ध पक्षकारों से उत्तर का अगोपनीय अंश, अनुरोध और उनके द्वारा प्रस्तुत/दिए गए साक्ष्य को ई-मेल द्वारा अन्य हितबद्ध पक्षकारों से साझा करने के लिए कहा गया था।
- vii. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को मौखिक रूप से सूचना प्रस्तुत करने का अवसर देने के लिए नियम 6(6) के अनुसार 12 जुलाई, 2022 को मौखिक सुनवाई आयोजित की, जिसके बाद लिखित अनुरोध करने थे। हितबद्ध पक्षकारों को अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत विचारों/सूचना के खंडन अनुरोध करने की अनुमति दी गई थी। प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त अनुरोधों पर उचित ढंग से विचार किया है।
- viii. इस जांच में अनिवार्य तथ्यों वाले एक प्रकटन विवरण, जो अंतिम जांच परिणामों का आधार बनेगा, को 29.08.2022 को जारी किया गया था और हितबद्ध पक्षकारों को उस पर टिप्पणी देने के लिए समय दिया गया था। प्रकटन विवरण के संबंध में, घरेलू उद्योग से प्राप्त टिप्पणियों पर इस अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना में संगत पाई गई सीमा तक विचार किया गया है।
- ix. प्राधिकारी ने जांच की प्रक्रिया के दौरान, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना, जो इस अंतिम जांच परिणाम का आधार है, की सटीकता से स्वयं को संभव सीमा तक संतुष्ट किया है और आवेदक द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों/दस्तावेजों को संगत, व्याख्यान और आवश्यक समझी गई सीमा तक सत्यापित किया है।
- x. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदत्त सूचना की गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई थी। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने जहां आवश्यक हो, गोपनीयता के दावे को स्वीकार किया

है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उसका प्रकटन नहीं किया है। जहां संभव हो, गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना का पर्याप्त अगोपनीय अंश प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था।

- xi. जहां कहीं भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने जांच की प्रक्रिया के दौरान आवश्यक सूचना देने से मना किया है या अन्यथा उसे उपलब्ध नहीं कराया है या जांच में अत्यधिक बाधा डाली है, वहां प्राधिकारी ऐसे पक्षकारों को असहयोगी माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर, अपने विचार दर्ज किए हैं।
- xii. इस अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना में ***चिन्ह किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई और नियमावली के अंतर्गत, प्राधिकारी द्वारा गोपनीय मानी गई सूचना को दर्शाता है।
- xiii. संबद्ध जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनिमय दर 1 अमरीकी डॉलर = 75.15 रुपए है।

ग. विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी)

10. मूल जांच के अनुसार तथा हाल में समाप्त हुई निर्णायक समीक्षा जांच के अनुसार भी विचाराधीन उत्पाद “90 प्रतिशत से कम सांद्रण वाला हाइड्रोजन पैरोआक्साइड” है। फूड ग्रेड और इलैक्ट्रानिक ग्रेड हाइड्रोजन पैरोआक्साइड पीयूसी के दायरे से बाहर हैं और इसके अलावा, 90 प्रतिशत और उससे अधिक सांद्रण के तकनीकी ग्रेड के हाइड्रोजन पैरोआक्साइड भी पीयूसी के दायरे से बाहर हैं। हाइड्रोजन पैरोआक्साइड का उत्पादन विभिन्न सांद्रणों में किया जा सकता है।
11. विचाराधीन उत्पाद को खुले और पैक, दोनों रूपों में बेचा जाता है। वाणिज्यिक रूप से इस उत्पाद को 35 प्रतिशत, 50 प्रतिशत, 60 प्रतिशत और 70 प्रतिशत सांद्रणों में उत्पादित और बेचा जाता है। इसे आमतौर पर 50 प्रतिशत आधार पर उत्पादित किया और बेचा जाता है। संबद्ध वस्तु सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के उप शीर्ष 28470000 के अंतर्गत अध्याय 28 के अधीन वर्गीकृत हैं। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक हैं और जांच के दायरे पर किसी भी तरह बाध्यकारी नहीं हैं।
12. चूंकि वर्तमान जांच संबंधित पाटनरोधी नियमावली के नियम 22 के अंतर्गत न्यू शिपर जांच है, इसलिए यह जांच मूल जांच में यथा-परिभाषित पीयूसी के निर्यातों से संबंधित है और यह बात हाल की निर्णायक समीक्षा जांच में भी मानी गई है।
13. आवेदक सहित किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा इस जांच में पीयूसी के दायरे और समान वस्तु के संबंध में कोई मुद्दा नहीं उठाया गया है।

घ. आवेदक और विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

14. आवेदक/उत्पादक/निर्यातक द्वारा किए गए अनुरोध:
 - i. आवेदक (संक्षिप्त रूप में अल-राजी) एडी नियमावली के नियम 22 में यथा-निर्धारित न्यू शिपर माने जाने की सभी अपेक्षाओं को पूरा करता है, इसका आधार डब्ल्यूटीओ एडी करार के अनुच्छेद 9.5 में है।
 - ii. अल-राजी ने मूल पाटनरोधी जांच की जांच अवधि के दौरान भारत को संबद्ध वस्तु का निर्यात नहीं किया है। उक्त जांच की पीओआई अप्रैल, 2014 से जून, 2015 तक थी और वास्तव में, अल-राजी जुलाई, 2018 में ही अधिनिगमन द्वारा अस्तित्व में आई थी और कंपनी ने मई, 2021 से ही संबद्ध वस्तु का उत्पादन शुरू किया है।
 - iii. अल-राजी निर्यातक देश में ऐसे किसी निर्यातक या उत्पादक से संबंधित नहीं है जो इस उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क के अधीन हों। समर्थक साक्ष्यों के साथ याचिका में विस्तृत अनुरोध दर्शाते हैं कि अल-राजी के पास संबद्ध वस्तु का ऐसा कोई संबंधित निर्यातक/उत्पादक नहीं है।

- iv. कानूनी अपेक्षाओं के अलावा, अल-राजी प्रक्रिया के अनुसार प्राधिकारी द्वारा देखी गई सभी अपेक्षाओं को पूरा करता है जिसमें न्यू शिपर आवेदन से पहले निर्यात शामिल हैं। अल-राजी ने एनएसआर की शुरुआत के बाद भारी मात्रा में संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है और यह मात्रा कंपनी के लिए अलग पाटन मार्जिन के निर्धारण हेतु वाणिज्यिक और पर्याप्त मात्रा है।
- v. यह अनुरोध किया जाता है कि प्राधिकारी कंपनी द्वारा उसके उत्तर में बताए गए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के संबंध में सूचना के आधार पर अल-राजी के लिए अलग मार्जिन निर्धारित कर सकते हैं।
- vi. यह ध्यान दिलाना भी संगत है कि प्राधिकारी ने मूल मामले में 0-20 प्रतिशत के बीच पाटन मार्जिन पाया था जबकि निर्णायक समीक्षा जांच में यह केवल 0-10 प्रतिशत पाया गया था। जब तक अल-राजी के लिए अलग मार्जिन निर्धारित नहीं होता है तब तक अल-राजी के निर्यातों पर मूल मामले में पाए गए उच्चतम पाटन मार्जिन के अनुसार एडीडी लगेगा जो किसी मामले में किसी भी समय न्यायोचित नहीं है और अल-राजी द्वारा बिल्कुल नहीं किया गया है। इसके मद्देनजर, सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के आधार पर अल-राजी के लिए अलग पाटन मार्जिन निर्धारित करना उचित होगा और कंपनी का इरादा भारत में उत्पाद के पाटन का कभी नहीं था।
- vii. 13 जून, 2022 से संबद्ध वस्तु पर लागू एडीडी की समाप्ति के होते हुए भी इस एनएसआर में अंतिम जांच परिणाम आवश्यक हैं। अल-राजी ने नियम के अंतर्गत यथा-अधिसूचित अनन्तिम आकलन के अधीन एनएसआर जांच शुरुआत का पालन करते हुए भारत को संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है तथा भारत में ऐसे निर्यातों/आयातों पर अंतिम शुल्क देयता एनएसआर के पूरा होने पर अंतिम जांच परिणाम के आधार पर ही निर्धारित हो सकती है।
- viii. जांच परिणाम के पूर्व-व्यापी प्रभाव के अलावा इस एनएसआर में जांच परिणाम की भावी प्रासंगिकता भी होगी क्योंकि घरेलू उद्योग द्वारा अपीलीय न्यायाधीकरण या किसी न्यायिक मंच के समक्ष एडीडी को जारी नहीं रखने के केन्द्र सरकार के निर्णय को चुनौती देने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।
- ix. प्राधिकारी भारत को संबद्ध वस्तु के अल-राजी के निर्यातों के आधार पर अलग मार्जिन निर्धारित कर सकते हैं और नियम के अंतर्गत यथा-अपेक्षित अधिसूचित कर सकते हैं। यद्यपि, एमओएफ द्वारा इस पर लेवी के आधार पर ऐसी सिफारिश अनन्तिम आकलन की अवधि के लिए वास्तविक शुल्क देयता के निर्धारण का आधार बन जाएगी, तथापि यह अनुरोध है कि अंतिम जांच परिणाम भी फा.सं. सीबीआईसी-190354/271/2021-टीओ (टीआरयू-1)-सीबीईसी दिनांक 22 जून, 2022 वाले वित्त मंत्रालय द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन के साथ पठित अंतिम जांच परिणाम फा.सं. 7/22/2021-डीजीटीआर दिनांक 11.3.2022 के साथ बने रहने की भी सिफारिश की जानी चाहिए।
- x. घरेलू उद्योग (डीआई) ने आवेदक के दावों पर कोई प्रश्न उठाने के लिए कोई वास्तविक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है और प्राधिकारी से केवल आवेदक की ओर से पूरी सूचना सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है। यह नोट किया जा सकता है कि अल-राजी द्वारा प्रस्तुत उत्तर और आवेदन में ऐसी समस्त सूचना है जो एनएसआर के रूप में उनके दावे को सही ठहराने के लिए पर्याप्त है तथा इसके मद्देनजर डीआई की आशंकाएं निराधार मानी जानी चाहिए।
- xi. यह तर्क कि पेट्रोल पोर्ट के ज़रिए निर्यातित सामग्री न्यूनतम मूल्य पर विचार करते हुए पुनः आकलन के अधीन है और निर्यात कीमत की कोई प्रासंगिकता नहीं है क्योंकि आवेदक केवल अपने ईक्यूआर के आधार पर पाटन मार्जिन के निर्धारण का अनुरोध करता है।
- xii. डीआई की एनएसआर की प्रकृति के बारे में आशंकाएं और तर्क तथ्यों से परे हैं और वर्तमान एनएसआर के संबंध में संदर्भ से बिल्कुल अलग हैं। आवेदक ने संशोधित आवेदन पत्र के अनुसार समस्त सूचना दी है और तत्पश्चात एक पूर्ण उत्तर प्रस्तुत किया है जो निर्यातक को बिल्कुल निश्चलक दर्शाता है और इसके विपरीत सभी तर्क केवल कयास हैं। एनएसआर भारतीय एडी नियमावली का हिस्सा है जिसका

डब्ल्यूटीओ एडी करार में भी आधार है और केवल डीआई के कयासों से किसी पात्र न्यू शिपर को एनएसआर के दर्जे से वंचित नहीं किया जा सकता।

15. घरेलू उद्योग/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

- i. घरेलू उद्योग को अल-राजी के लिए अलग पाटन मार्जिन के निर्धारण पर कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते कि निर्यातक ने पूरी और सही सूचना प्रस्तुत की हो और न्यू शिपर के रूप में अपनी पात्रता सिद्ध की हो।
- ii. इस बात पर विचार करते हुए कि संबद्ध वस्तु पर लागू पाटनरोधी शुल्क 9 जून, 2022 से पहले ही समाप्त हो गया है, घरेलू उद्योग मानता है कि यदि केन्द्र सरकार पाटनरोधी शुल्क की अवधि नहीं बढ़ाती है तो इस समीक्षा की कोई उपयोगिता नहीं है।
- iii. पेट्रापोल पोर्ट में प्रवेश करने वाले बंगलादेश के आयात आकलन योग्य मूल्य पर डीजीसीआई एंडएस द्वारा सूचित किए गए हैं जो वास्तविक बीजक मूल्य से काफी अधिक हैं। यद्यपि, अन्य पत्तनों पर प्रवेश करने वाली संबद्ध वस्तु की कीमत 26,349 रु./एमटी है, तथापि पेट्रापोल पोर्ट में प्रवेश करने वाले आयातों की कीमत 30,957 रु./एमटी है। अतः यह अनुरोध किया गया है कि पेट्रापोल पोर्ट से आने वाले आयातों के मामलों में सीमा शुल्क आंकड़ों में सूचित कीमत पर पाटन मार्जिन के निर्धारण हेतु विचार नहीं किया जाना चाहिए और इसकी प्रति-जांच की जानी चाहिए तथा निर्यातक द्वारा प्रस्तुत सूचना से विस्तृत सत्यापन किया जाए।
- iv. प्राधिकारी ने हाल की अनेक जांचों में आयातों की कम मात्रा के निष्कर्ष पर अलग पाटन मार्जिन से इंकार किया है। इसके अलावा, विभिन्न अन्य देश भी अलग पाटन मार्जिन के निर्धारण से पहले आयातों की तर्कसंगत मात्रा पर जोर देते हैं। अतः प्राधिकारी, निर्यातक द्वारा दावा की गई निर्यात कीमत की विश्वसनीयता, आधार, सत्यता और उचित होने का पता लगा सकते हैं। घरेलू उद्योग को इस संबंध में काफी तथ्यों को छुपाए जाने की आशंका है।

ड. प्राधिकारी द्वारा जांच

16. पाटनरोधी नियमावली के नियम 22 में निम्नानुसार प्रावधान है:

नियम 22. मूल रूप से जांच नहीं किए गए निर्यातक के लिए पाटन मार्जिन - (1) यदि किसी उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क लगाया जाता है, तो निर्दिष्ट प्राधिकारी संबंधित निर्यातक देश के किसी भी निर्यातक अथवा उत्पादक, जिसने जांच की अवधि के दौरान भारत को उस उत्पाद का निर्यात नहीं किया है, के लिए अलग-अलग पाटन मार्जिन के निर्धारण के प्रयोजनार्थ आवधिक समीक्षा करेंगे, बशर्ते ये निर्यातक अथवा उत्पादक यह सिद्ध करते हैं कि वे निर्यातक देश के किसी निर्यातक अथवा उत्पादक से सम्बद्ध नहीं हैं, जिन पर उस उत्पाद हेतु पाटनरोधी शुल्क लगाया गया है।

(2) केन्द्रीय सरकार इस नियम के उप नियम (1) में यथा संदर्भित निर्यातकों अथवा उत्पादकों से किए गए आयातों पर जांच अवधि के दौरान अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (1) के अंतर्गत पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण नहीं करेगी।

बशर्ते कि केन्द्रीय सरकार अनंतिम आकलन करे और यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी ऐसी संस्तुति करते हों तो आयातक से गारंटी प्राप्त करे और यदि ऐसी समीक्षा की परिणति ऐसे उत्पादों अथवा निर्यातकों के संबंध में पाटन के निर्धारण में होती हो, तो ऐसे मामलों में वह समीक्षा की शुरुआत की तारीख से, भूतलक्षी प्रभाव से शुल्क अधिरोपित करेगी।

1/(3) सहयोगी गैर-प्रतिदर्शित निर्यातकों या उत्पादकों के लिए पहले से लागू पाटनरोधी शुल्क को ऐसे निर्यातकों या उत्पादकों पर भी लगाया जा सकता है जिनकी मूल रूप से जांच नहीं की गई थी।

1a [स्पष्टीकरण***]

17. विश्व व्यापार संगठन के पाटन-रोधी करार के अनुच्छेद 9.5 में उल्लिखित प्रावधान निम्नानुसार है:-

"9.5 यदि कोई उत्पाद आयातक सदस्य में पाटनरोधी शुल्क के अधीन हो तो प्राधिकारी जाँच के अधीन निर्यातक देश में ऐसे किसी निर्यातक या उत्पादक के लिए पाटन के अलग मार्जिन के निर्धारण के प्रयोजनार्थ तत्काल समीक्षा करेंगे जिसने जाँच अवधि के दौरान आयातक सदस्य को उत्पाद का निर्यात नहीं किया हो बशर्ते कि ये निर्यातक या उत्पादक यह दर्शा सकता हो कि वे निर्यातक देश में ऐसे किसी निर्यातक या उत्पादक से संबंधित नहीं हैं जो उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क के अधीन हैं। ऐसी कोई समीक्षा आयातक सदस्य में सामान्य शुल्क निर्धारण और समीक्षा कार्यवाही की तुलना में सक्रिय आधार पर शुरू की जाएगी और चलाई जाएगी। समीक्षा के दौरान ऐसे निर्यातकों या उत्पादकों से आयातों पर कोई पाटनरोधी शुल्क नहीं लगाया जाएगा। तथापि, प्राधिकारी मूल्यांकन को रोक सकते और/या यह सुनिश्चित करने के लिए गारंटी का अनुरोध कर सकते हैं कि यदि ऐसी समीक्षा के परिणामस्वरूप ऐसे उत्पादकों या निर्यातकों के संबंध में पाटन का निर्धारण होता है तो पाटनरोधी शुल्क को समीक्षा की शुरुआत की तारीख से पूर्वव्यापी प्रभाव से लगाया जा सके।"

18. पूर्वोक्त नियम के अनुसार डब्ल्यूटीओ करार के प्रावधानों और प्राधिकारी की पूर्ववर्ती परिपाटी के अनुसार कोई न्यू शिपर समीक्षा जांच पाटनरोधी शुल्क लगे हुए संबद्ध देश से किसी निर्यातक या उत्पादक के संबंध में अलग पाटन मार्जिन के निर्धारण के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित परिस्थितियों में की जाएगी:

- i. यह कि निर्यातक या उत्पादक ने जांच अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद का निर्यात नहीं किया है, और
- ii. यह कि निर्यातक या उत्पादक दर्शाता हो कि वे निर्यातक देश में ऐसे किसी निर्यातक या उत्पादक से संबंधित नहीं हैं जो संबंधित उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क के अधीन हैं।

19. वर्तमान मामले में मैसर्स अल-राजी केमिकल कांप्लेक्स लिमिटेड, बंगलादेश (उत्पादक/निर्यातक) ने प्राधिकारी के समक्ष "हाइड्रोजन पैराआक्साइड" के निर्यातों से संबंधित अलग पाटन मार्जिन की मांग करते हुए एक आवेदन प्रस्तुत किया है और न्यू शिपर समीक्षा की शुरुआत हेतु अनुरोध किया है।

20. 'एनएसआर' के दावे के लिए उत्पादक/निर्यातक की पात्रता के संबंध में प्राधिकारी ने उत्पादक/निर्यातक द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों/सूचना के संबंध में प्रस्तुत विभिन्न दस्तावेजों के टेबल अध्ययन सहित उत्पादक/निर्यातक द्वारा किए गए दावों की विस्तृत जांच की है। ऐसी जांचें नियम 22 और प्राधिकारी की पूर्ववर्ती परिपाटी की अपेक्षाओं के मद्देनजर की गई थी। किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने कानूनी अनुरोधों से इतर किसी पर्याप्त साक्ष्य के माध्यम से एनएसआर के लिए उत्पादक/निर्यातक द्वारा शर्तों को पूरा नहीं करने का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। अतः प्राधिकारी, मानते हैं कि यह उत्पादक/निर्यातक वर्तमान मामले में न्यू शिपर समीक्षा की मांग करने का पात्र है।

21. संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु पर पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति के मद्देनजर इस मामले में अंतिम जांच परिणाम की प्रासंगिकता संबंधी तर्क के बारे में प्राधिकारी नोट करते हैं कि नियम 22 के अंतर्गत जांच शुरू की गई थी जबकि शुल्क लागू थे और जांच को किसी तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए अंतिम जांच परिणाम अनिवार्य हैं जो उस अवधि के दौरान अनंतिम आकलन के लिए वास्तविक शुल्क देयता निर्धारित करने के लिए विशेष रूप से अनिवार्य होंगे, जिसके दौरान आवेदक ने वास्तविक एडीडी के भुगतान के बिना आयात किया था।

22. इस तर्क के संबंध में कि पेट्रापोल पोर्टों के रास्ते आयातों को पुनः आकलन के अधीन रखा जाए, प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत संबंधी सत्यापित सूचना के आधार पर उनके उत्तर में प्रस्तुत आवेदक के लिए अलग मार्जिन निर्धारित किया है।

च. आवेदक के लिए अलग पाटन मार्जिन का निर्धारण

23. आवेदक के लिए अलग पाटन मार्जिन के निर्धारण हेतु आवेदक द्वारा जांच की शुरुआत के लिए आवेदन में दिए गए आंकड़ों/अनुरोधों तथा सत्यापन की प्रक्रिया के दौरान तत्पश्चात प्रस्तुत आंकड़ों की जांच की गई थी। तत्संबंधी समुक्तियां निम्नानुसार हैं:

- i. आवेदक ने दिनांक *** के अपने आवेदन में *** से *** तक की अवधि के लिए घरेलू बिक्रियों के ब्यौरे प्रस्तुत किए थे (आवेदन का अनुबंध-4)। तत्पश्चात, आवेदक ने एक ईक्यूआर प्रस्तुत किया है जिसमें *** से *** तक की अवधि के लिए घरेलू बिक्रियां दी गई हैं (परिशिष्ट-4क)। इन दोनों की तुलना की गई और यह नोट किया गया है कि आरंभिक आवेदन में बताए गए ***घरेलू बिक्री सौदों में से केवल ***सौदे ईक्यूआर के परिशिष्ट-4क में प्रस्तुत सौदों से मेल खाते हैं। उत्पादक/निर्यातक से घरेलू बिक्रियों में इस असमानता के लिए औचित्य/स्पष्टीकरण प्रदान करने का अनुरोध किया गया था। इसके उत्तर में, उत्पादक-निर्यातक ने दिनांक *** के ई-मेल द्वारा बताया कि एनएसआर आवेदन के साथ प्रस्तुत बिक्री आंकड़े सही नहीं थे क्योंकि इन आंकड़ों को प्रपत्र बीजको के अनुसार तैयार किया गया था और न कि वाणिज्यिक बीजकों के अनुसार। यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आवेदन *** को प्रस्तुत किया गया और *** को किए गए घरेलू बिक्री सौदे भी मेल नहीं खाते हैं।
- ii. इसके अलावा, ईक्यूआर में प्रस्तुत लागत आंकड़े (*** को) को *** के आंकड़ों के सत्यापन के समय प्रस्तुत अपने अनुरोध में उत्पादक-निर्यातक द्वारा काफी अधिक बदल दिया गया है। प्राधिकारी ने आंकड़ों में इस बदलाव का कारण पूछा था और उसके औचित्य संबंधी उत्तर में उत्पादक-निर्यातक ने दिनांक *** के ई-मेल द्वारा यह बताया कि परिशिष्ट 7 को ईक्यूआर प्रस्तुत करते समय अलेखा-परीक्षित बहियों से तैयार किया गया था, जबकि सत्यापन के समय के आंकड़े लेखा परीक्षित लेखाओं पर आधारित थे जिनमें कुछ खर्च जोड़े गए थे। यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कच्ची सामग्री, सुविधाओं, पैकिंग आदि के आंकड़ों में भारी बदलाव किया गया है जिसके परिणामस्वरूप *** करोड़ बीडीटी का घाटा *** करोड़ बीडीटी के लाभ में बदल गया है। इसके अलावा, *** से *** की अवधि के लिए पूर्ववर्ती वर्ष के आंकड़े भी बदले गए हैं और पूर्ववर्ती वर्ष का *** करोड़ बीडीटी का घाटा बदलकर *** करोड़ बीडीटी का लाभ हो गया है।

24. अतः प्राधिकारी ने मैसर्स अल-राजी केमिकल कांप्लेक्स लिमिटेड, बंगलादेश (उत्पादक/निर्यातक) द्वारा दायर उत्तर अस्वीकार करने का निर्धारण किया है।

छ. प्रकटन पश्चात टिप्पणियाँ

छ.1 आवेदक/उत्पादक/निर्यातक द्वारा अनुरोध:

25. आंकड़ों में विसंगति खातों को अंतिम रूप देने में विलंब और कंपनी के अधिकारियों के अंत में आंकड़ों की रिपोर्टिंग करते समय देखी जाने वाली तकनीकी अपेक्षाओं की समझ की कमी के कारण रिपोर्टिंग में कुछ मानवीय त्रुटियों के कारण हुई है, जो केवल अंतिम रूप से जानकारी में आ सकती थी और इन स्वीकार की गई त्रुटियों के कारण आवेदक द्वारा खुद दायर किए गए उत्तर को रद्द नहीं किया जाना चाहिए, जैसा कि प्रस्ताव किया गया है।
26. बिक्री के आंकड़ों में बेमेल के पहले मुद्दे के संबंध में, बिक्री की रिपोर्टिंग आवेदन के समय की गई थी, अफसोस की बात है कि प्रोफार्मा बीजक के आधार पर अंतिम रूप से प्राप्त किया गया था और चूंकि अधिकारी ने रिपोर्टिंग शुरू की उसके बाद नौकरी छोड़ दी, अतः यह असंगतता हो सकती है इस पर तुरंत ध्यान नहीं दिया गया और आवेदक ने गलत नंबरों की सूचना दी जो वाणिज्यिक बीजकों के अनुसार नहीं थे। यह नोट किया जाए कि कंपनी का किसी भी गलत रिपोर्टिंग का कोई इरादा नहीं था और असंगति केवल एक मानवीय त्रुटि रही है।
27. तथापि, सत्यापन से पहले प्राधिकारी को सही सत्यापनीय बिक्री आंकड़े प्राप्त कराए गए थे और यह सादर प्रार्थना की जाती है कि प्राधिकारी कृपया अब संशोधित आंकड़ों को अपनाएं और संपूर्ण प्रतिक्रिया को अस्वीकार करने के बजाय आवेदक के लिए मार्जिन निर्धारित करें। आंकड़ों में बेमेल से इस मामले में अब तक मार्जिन का कोई गलत निर्धारण नहीं हुआ है और इस तरह की मानवीय त्रुटि को क्षमा करना केवल न्याय और निष्पक्ष व्यापार के हित में होगा।

28. दूसरी इस टिप्पणी के संबंध में कि पिछले वर्ष सहित आंकड़ों के सत्यापन के समय दायर किए गए अपने अनुरोधों में निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर में दायर लागत आंकड़ों को उत्पादक-निर्यातक द्वारा काफी हद तक बदल दिया गया है, यह सादर अनुरोध किया जाता है कि लागत संबंधी आंकड़ों में खेदजनक विसंगतता लेखापरीक्षा प्रक्रिया में विलंब और लेखापरीक्षा प्रक्रिया के भाग के रूप में हुई लागत मदों को मानने में कुछ पर्याप्त परिवर्तनों के परिणामस्वरूप हुई है। कोविड प्रतिबंधों के कारण लेखापरीक्षा में विलंब हुआ और पिछले वर्ष के लिए भी लेखापरीक्षा में विलंब का यही कारण था। प्राधिकारी ने पिछले वर्ष भी इस तरह के विलंब को व्यावहारिक रूप से नोट किया था। तथापि, यह नोट किया जाए कि ऐसी कठिनाइयों को देखते हुए, बांग्लादेश के राष्ट्रीय राजस्व बोर्ड ने कंपनी के लिए आकलन वर्ष 2021-2022 के लिए आयकर रिटर्न भरने की समय सीमा 15 जून, 2022 तक बढ़ा दी है।
29. संगत भाग के अनुवाद के साथ संगत अधिसूचना प्राधिकारी को उपलब्ध कराई गई है। प्राधिकारी यह भी नोट करें कि कंपनी ने हाल के दिनों में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया है और कुछ लागत मदों आदि में परिवर्तन के सुधार इस संदर्भ में देखे जाने की आवश्यकता है क्योंकि प्रक्रिया तैयार की जा रही थी और प्रभावी थी।
30. सत्यापन से पहले प्रस्तुत किए गए लेखापरीक्षित अभिलेखों के आधार पर अंतिम लागत आंकड़े पूरी तरह से विश्वसनीय और प्रामाणिक हैं तथा यह हमारी सादर प्रार्थना है कि इस विसंगति का उल्लेख करने पर भी, प्राधिकारी यह नोट करें कि विसंगतता गलती से हुई थी और केवल लागत व्यवहार में परिवर्तनों के कारण हुई थी तथा आवेदक ने कभी भी कोई गलत आंकड़े उपलब्ध कराने का सहारा नहीं लिया जिससे प्राधिकारी द्वारा गलत निर्धारण हो।
31. आंकड़ों में त्रुटियों को सुधारने का अवसर प्राधिकारी के समक्ष जांच प्रक्रिया का बहुत बड़ा भाग है और कृपया यह माना जाए कि आवेदक ने सत्यापन से पहले आंकड़ों में कुछ विसंगतियों को स्वयं ही ठीक कर लिया है। इस मामले में अंतिम जांच परिणाम के प्रयोजन के लिए प्राधिकारी के पास अंतिम और सत्यापनीय लेखापरीक्षित सूचना है तथा कृपया ऐसे परिदृश्य में उत्तर को रद्द करने से बचा जाए।

छ.2 घरेलू उद्योग/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध:

32. घरेलू बिक्री आंकड़ों और उत्पादन आंकड़ों की लागत में आवेदन पत्र दायर करने के समय और सत्यापन के समय के बीच काफी अधिक परिवर्तन हुए हैं। प्रकटन विवरण से यह भी बहुत स्पष्ट है कि जहां आवेदक ने पहले सूचित किया था कि उसे वित्तीय हानियां हुई हैं, अब यह सूचित किया गया है कि उसने लाभ अर्जित किया है।

छ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

33. प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक ने आंकड़ों में भिन्नता होना स्वीकार किया है और त्रुटि को स्वीकार किया है, लेकिन यह कहा है कि यह भिन्नता खातों को अंतिम रूप देने में विलंब और कंपनी के अधिकारियों के स्तर पर आंकड़ों की रिपोर्टिंग करते समय पालन की जाने वाली तकनीकी अपेक्षाओं की समझ के अभाव के कारण रिपोर्टिंग में कुछ मानवीय त्रुटियों के कारण थी। आवेदक ने यह भी उल्लेख किया है कि बिक्री की रिपोर्टिंग आवेदन के समय की गई थी, अफसोस की बात है कि प्रोफार्मा बीजक के आधार पर अंतिम रूप से प्राप्त किया गया था और चूंकि अधिकारी ने रिपोर्टिंग शुरू की, उसके बाद नौकरी छोड़ दी, अतः यह असंगतता हो सकती है, इस पर तुरंत ध्यान नहीं दिया गया और आवेदक ने गलत नंबरों की सूचना दी जो वाणिज्यिक बीजकों के अनुसार नहीं थे। तथापि, सत्यापन से पहले प्राधिकारी को सही सत्यापनीय बिक्री आंकड़े प्राप्त कराए गए थे। इस टिप्पणी के संबंध में कि पिछले वर्ष सहित आंकड़ों के सत्यापन के समय दायर किए गए अपने अनुरोधों में निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर में दायर लागत आंकड़ों को उत्पादक-निर्यातक द्वारा काफी हद तक बदल दिया गया है, आवेदक ने यह अनुरोध किया है कि लागत संबंधी आंकड़ों में खेदजनक विसंगतता लेखापरीक्षा प्रक्रिया में विलंब और लेखापरीक्षा प्रक्रिया के भाग के रूप में हुई लागत मदों को मानने में कुछ पर्याप्त परिवर्तनों के परिणामस्वरूप हुई है। कोविड प्रतिबंधों के कारण लेखापरीक्षा में विलंब हुआ और पिछले वर्ष के लिए भी लेखापरीक्षा में विलंब का यही कारण था। प्राधिकारी का यह मत है कि आवेदक का यह स्पष्टीकरण कि मानवीय त्रुटि के कारण आंकड़ों की रिपोर्ट करने में त्रुटि हुई और कंपनी के अधिकारियों के स्तर पर आंकड़ों की रिपोर्ट करते समय तकनीकी अपेक्षाओं की समझ की

कमी देखी गई, एक ठोस तर्क नहीं है। और इसलिए अस्वीकार्य है। साथ ही, प्राधिकारी का यह भी मत है कि आवेदक का यह स्पष्टीकरण कि निर्यातक प्रश्नावली के उत्तरों में दायर लागत आंकड़ों में खेदजनक विसंगतता लेखापरीक्षा प्रक्रिया में विलंब और लेखापरीक्षा के भाग के रूप में होने वाली लागत मदों के सुधार में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तनों का परिणाम है। यह प्रक्रिया भी प्रशंसनीय और उचित तर्क नहीं है। इस प्रकार प्राधिकारी आवेदक के स्पष्टीकरण को स्वीकार नहीं करते हैं। अतः, प्राधिकारी ने मैसर्स अल-रज़ी केमिकल कॉम्प्लेक्स लिमिटेड, बांग्लादेश (उत्पादक/निर्यातक) द्वारा दायर किए गए उत्तर को अस्वीकार करने का निर्णय लिया है।

ज. निष्कर्ष एवं सिफारिश

34. मैसर्स अल-रज़ी केमिकल कॉम्प्लेक्स लिमिटेड, बांग्लादेश (उत्तर/निर्यातक) और घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोधों की जांच करने और रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों पर विचार करने के बाद, प्राधिकारी ने यह निष्कर्ष निकालते हैं कि आवेदक का यह स्पष्टीकरण कि रिपोर्टिंग में त्रुटि मानवीय त्रुटि और कंपनी के अधिकारियों के स्तर पर आंकड़ों की रिपोर्टिंग करते समय देखी जाने वाली तकनीकी अपेक्षाओं की समझ की कमी के कारण हुई और यह कि निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर में दायर लागत संबंधी आंकड़ों में खेदजनक विसंगतता लेखापरीक्षा प्रक्रिया में विलंब का परिणाम है। और लेखापरीक्षा प्रक्रिया के भाग के रूप में होने वाली लागत मदों के सुधार में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन प्रशंसनीय और उचित स्पष्टीकरण नहीं है। इस प्रकार प्राधिकारी मैसर्स अल-रज़ी केमिकल कॉम्प्लेक्स लिमिटेड, बांग्लादेश द्वारा दायर उत्तर को अस्वीकार करने का निर्णय लेते हैं और मैसर्स अल-रज़ी केमिकल कॉम्प्लेक्स लिमिटेड, बांग्लादेश को व्यक्तिगत शुल्क नहीं देने की सिफारिश करते हैं।

झ. आगे की प्रक्रिया

35. इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए आयात का पहुंच मूल्य सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के तहत सीमा शुल्क द्वारा निर्धारित निर्धारणीय मूल्य होगा और इसमें उक्त अधिनियम की धारा 3, 3क, 8ख, 9 और 9क के तहत शुल्क को छोड़कर सीमा शुल्क के सभी शुल्क शामिल हैं।
36. इस जांच परिणाम के कारण होने वाले केंद्र सरकार के आदेश के विरुद्ध कोई अपील सीमा शुल्क अधिनियम के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय अधिकरण के समक्ष की जाएगी।

अनन्त स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th September, 2022

Final Findings

Case No. A.D (NSR)-01/2021

Subject: New Shipper Review under Rule 22 of Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended, pertaining to anti-dumping duty imposed on the imports of “Hydrogen Peroxide” originating in or exported from Bangladesh, as requested by M/s Al-Razi Chemical Complex Limited, Bangladesh (Producer/Exporter), initiated on 10.09.2021.

No. 7/25/2021-DGTR: Having regard to the Customs Tariff Act 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the “Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the “Rules”) thereof;

A. BACKGROUND OF THE CASE

2. An original anti-dumping investigation was initiated on 14th January, 2016 by the Designated Authority (hereinafter also referred to as the “Authority”) to examine the nature and the extent of the dumping and its

injurious effect on the domestic industry with respect to the import of “Hydrogen Peroxide” (hereinafter also referred to as the “subject goods” or the “Product Under Consideration”) originating in or exported from Bangladesh, Taiwan, Korea RP, Indonesia, Pakistan and Thailand (hereinafter also referred to as the “subject countries”). The Authority, vide its final findings notification no. 14/03/2015- DGAD dated 11th April, 2017 recommended imposition of the anti-dumping duties on these countries, except Indonesia, which were given effect by the Central Government (Department of Revenue, Ministry of Finance) vide Customs Notification No. 28/2017-Customs (ADD) dated 14th June, 2017 for a period of five years.

3. The said final findings notification was assailed before the Hon'ble CESTAT. Thereafter, in pursuance to the Hon'ble CESTAT's Order No. 58470-58474/2017 dated 20th December, 2017, revised final findings were notified by the Authority vide notification no. 14/03/2015-DGAD dated 17th April, 2018. In the revised findings the Authority re-determined the Non-Injurious Price (NIP) and recommended the revised quantum of the anti-dumping duty on the imports of “Hydrogen Peroxide” originating in or exported from the subject countries. On the basis of the recommendations made by the Authority, definitive anti-dumping duty was imposed by the Central Government vide Notification No. 33/2018-Customs (ADD) dated 1st June, 2018 for a period of five years. The duties so levied were set to expire on 13th June, 2022, unless extended further.
4. M/s Al-Razi Chemical Complex Limited, Bangladesh (Producer/Exporter), filed an application for New Shipper Review (NSR) in terms of Rule 22 of the Anti-dumping Rules read with the Customs Tariff Act, requesting for a New Shipper Review (NSR) in respect of the imports of the “Hydrogen Peroxide” originating in or exported from Bangladesh, claiming individual dumping margin for M/s Al-Razi Chemical Complex Limited in respect of the exports of the Hydrogen Peroxide made by it.
5. The Authority, having been prima facie satisfied with the conditions laid down under Rule 22 of the Anti-dumping Rules, initiated a new shipper review investigation, vide Notification No.7/25/2021-DGTR dated 10th September, 2021 for determination of individual dumping margin for the purpose of imposition of the anti-dumping duty to be levied on the imports of Hydrogen Peroxide originating in or exported from Bangladesh, in respect of M/s Al-Razi Chemical Complex Limited, Bangladesh (Producer/Exporter).
6. The Ministry of Finance notified vide Notification No.72/2021-Customs (ADD) dated 17th December, 2021 the provisional assessment on all exports of the subject goods made by M/s Al-Razi Chemical Complex Limited, Bangladesh (Producer/Exporter), till completion of the aforesaid NSR investigation.
7. The period of investigation (POI) for the purpose of this NSR was fixed as 1st April, 2021 to 31st December, 2021.
8. Notwithstanding the above, sunset review of anti-dumping duties applicable on “Hydrogen Peroxide” originating in or exported from Bangladesh and Thailand was conducted by the Authority based on an application filed by the domestic industry and the final findings notification for continuation of the duties was notified vide File No. 7/22/2021-DGTR dated 11th March 2022. However, the Ministry of Finance vide Office Memorandum No. CBIC-190354/271/2021-TO (TRU-1)-CBEC dated 22nd June, 2022 communicated that the Central Government has decided, after considering the recommendations of the Designated Authority, not to accept the recommendations for continued imposition of duties notified vide File No. 7/22/2021-DGTR dated 11th March, 2022. As a result of the said decision, the anti-dumping duties levied on the subject goods including that from Bangladesh stands expired with effect from 13th June, 2022.

B. PROCEDURE FOLLOWED IN THE INVESTIGATION

9. The procedure described below has been followed with regard to the present investigation:
 - i. The Authority issued a public notice vide Notification No. 7/25/2021-DGTR dated 10th September, 2021 published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating the subject NSR anti-dumping investigation.
 - ii. The Authority forwarded a copy of the initiation notification to the applicant along with a copy of the exporter's questionnaire and gave it the opportunity to make its views known in writing and filing relevant data in the prescribed questionnaire after the expiry of the POI.
 - iii. The Authority also forwarded a copy of the initiation notification to the High Commission of Bangladesh in India.
 - iv. The Authority forwarded a copy of the initiation notification to the known domestic producers in India and gave them an opportunity to make their views known in writing. A copy of the non-confidential version of the application was also provided to the interested parties through email.
 - v. In response to the initiation notification, the exporter questionnaire response was filed by M/s Al-Razi Chemical Complex Limited, Bangladesh (Producer/Exporter) {NSR Applicant}. National Peroxide Limited representing the domestic industry of “Hydrogen Peroxide” in India and an importer/user/trader, namely, Sandeep Organics Ltd expressed their interest in the present NSR investigation.

- vi. Since physical movement is curtailed due to Covid-19 pandemic, all the interested parties were asked to share the non-confidential version of the responses, submissions and evidence submitted/presented by them with the other interested parties by email.
- vii. The Authority held an oral hearing on 12th July, 2022 to provide an opportunity to the interested parties to present information orally in accordance with Rule 6(6) followed by the written submissions. The interested parties were allowed to present rebuttal/rejoinders on the views/information presented by the other interested parties. The Authority has considered submissions received from the interested parties appropriately.
- viii. A disclosure statement containing the essential facts in this investigation which would have been formed the basis of the final findings was issued on 29.08.2022 and the interested parties were allowed time to comment on the same. The comments on the disclosure statement received from the domestic industry have been considered, to the extent found relevant, in this final finding notification.
- ix. The Authority, during the course of the investigation, satisfied itself as to the accuracy of the information supplied by the interested parties, which forms the basis of this final finding to the extent possible and verified the data/documents submitted by the applicant to the extent considered relevant, practicable and necessary.
- x. The information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to the sufficiency of the confidentiality claims. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted, and such information has been considered as confidential and not disclosed to the other interested parties. Wherever possible, the parties providing the information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.
- xi. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such interested parties as non-cooperative and recorded the final findings on the basis of the facts available.
- xii. *** in the final finding notification represents information furnished by an interested party on confidential basis, and so considered by the Authority under the Rules.
- xiii. The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is US\$1= Rs.75.15

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION (PUC)

- 10. The product under consideration as per the original investigation and also the recently concluded sunset review investigation is "hydrogen peroxide of concentration below 90%". Food grade and electronic grade hydrogen peroxide is beyond the scope of the PUC and further, hydrogen peroxide of technical grade of concentration 90% and above is also beyond the scope of the PUC. Hydrogen peroxide can be produced in different concentrations.
- 11. The product under consideration is sold in both loose and packed conditions. Commercially, the product is produced and sold in 35%, 50%, 60% and 70% concentration. It is generally produced and sold on 50% basis. Subject goods are classified under Chapter 28 under sub heading 28470000 of Customs Tariff Act, 1975. The customs classification is indicative only and in no way, it is binding on the scope of the investigation.
- 12. Since the present investigation is a new shipper investigation under Rule 22 of the Anti-dumping Rules supra, the investigation pertains to the exports of the PUC as defined in the original investigation and as upheld in the recent sunset review investigation.
- 13. There are no issues on the scope of the PUC or like article as such raised in this investigation by any of the interested parties including the applicant.

D. SUBMISSIONS BY THE APPLICANT AND VARIOUS INTERESTED PARTIES:

- 14. Submissions by the applicant/producer/exporter:
 - i. The applicant (Al-Razi in short) meets all the requirements to be treated as a new shipper as stipulated in Rule 22 of the AD Rules which has its basis in Article 9.5 of the WTO Anti-dumping Agreement.
 - ii. Al-Razi did not export the subject goods to India during the period of investigation of the original anti-dumping investigation. The POI of the said investigation was from April, 2014 to June, 2015 and, in fact, Al-Razi came into existence by incorporation in July, 2018 only and the company commenced production of the subject goods from May, 2021 only.
 - iii. Al-Razi is also not related to any of the exporters or producers in the exporting country who are subjected to the anti-dumping duties on the product. The detailed submissions in the petition along with supporting evidences demonstrates that Al-Razi has no such related exporters/producers of the subject goods.

- iv. Apart from the legal requirements, Al-Razi fulfils the requirements observed by the Authority as a matter of practice which includes exports prior to the new shipper application. Al-Razi has exported significant volume of the subject goods post initiation of the NSR and the volume is commercial and substantial in quantity to determine individual margin for the company.
- v. It is requested that the Authority may determine individual margin for Al-Razi based on the information on the normal value and the export price shared by the company in its response.
- vi. It is also relevant to point out that the Authority found dumping margin in the range of 0-20% in the original case which was found as 0-10% only in the sunset review investigation. Until an individual margin is determined for Al-Razi, the exports by Al-Razi will attract ADD as per the highest dumping margin found in the original matter which is not justified at all at this point of time in any case and such dumping is not followed by Al-Razi at all. In view of the same, it shall be fair to determine an individual margin for Al-Razi based on its normal value and the export price and the company never intended to dump the product in India.
- vii. Notwithstanding the expiry of the applicable ADD on the subject goods with effect from 13th June, 2022, a final finding is necessary in this NSR. Al-Razi exported the subject goods to India following the NSR initiation subject to provisional assessment as notified under the Rule and the final duty liability on such exports/imports into India can only be determined based on a final finding on completing the NSR.
- viii. Apart from the retrospective effect of the findings, final findings in this NSR have prospective relevance also as the chances of domestic industry assailing the decision of the Central Government not to continue the ADD before an appellate authority or any judicial forum cannot be ruled out.
- ix. The Authority may determine the individual margin for Al-Razi based on its exports of the subject goods to India and notify the same as required under the Rule. While such a recommendation, upon levy of it by the MOF, shall become the basis for determination of the actual duty liability for the period of provisional assessment, it is requested that the final findings also must be recommended to coexist with the final finding notification no. 7/22/2021-DGTR dated 11.3.2022 read with Office Memorandum issued by the Ministry of Finance bearing File No. CBIC-190354/271/2021-TO (TRU-1)-CBEC dated 22nd June, 2022.
- x. The domestic industry (DI) has not brought on record any material evidences to dispute any of the claims of the applicant and has only requested the Authority to ensure complete information from the side of the applicant. It can be noted that the response and application filed by Al-Razi contain all the relevant information which is sufficient to substantiate the claim as in NSR and, in view of the same, the apprehensions of the DI should be noted as out of place.
- xi. The contention that the material exported through Petrapole port is subjected to reassessment considering a minimum value and export price has no relevance as the applicant requests determination of dumping margin based on its EQR alone.
- xii. The apprehensions and contentions of the DI about the nature of NSR as such have no merit and are completely out of context as far as it pertains to the present NSR. The applicant has submitted all the information as per the revised application format and a complete response is also filed thereafter, which shows the exporter has come with clean hands and contention to the contrary are all merely speculative. NSR is part of the Indian AD Rules which have basis in the WTO AD Agreement and mere speculations by the DI cannot lead to denial of NSR status to an eligible new shipper.

15. Submissions by the domestic industry/other interested parties:

- i. The domestic industry does not have any objection to determination of individual dumping margin for Al Razi provided that the exporter has submitted complete and accurate information and established its eligibility as a new shipper.
- ii. Considering that the anti-dumping duty imposed on the subject goods has already expired with effect from 9th June 2022, the domestic industry considers that this review is of no utility, unless the Central Government extends the anti-dumping duty.
- iii. The imports from Bangladesh entering at Petrapole Port are reported by the DGCI&S at assessable value which is considerably higher than the actual invoice value. While the subject goods entering the other ports are priced as Rs. 26,349/MT, the imports entering at Petrapole Port are priced at Rs. 30,957/MT. It is, therefore, requested that in case of the imports entering at Petrapole Port, the prices reported in the customs data should not be considered for determination of the dumping margin and the same may kindly be cross-checked and verified in detail from the information submitted by the exporter.

- iv. The Authority has, in a large number of recent investigations, denied individual dumping margin on finding low volume of imports. Further, various other countries also insist on reasonable volume of imports before determining an individual dumping margin. The Authority may, therefore, ascertain credibility, reliability, appropriateness, and correctness of the export price claimed by the exporter. The domestic industry apprehends significant suppression of facts on this account.

E. EXAMINATION BY THE AUTHORITY

16. Rule 22 of the Anti-Dumping Rules provides as follows –

Rule 22. Margin of dumping, for exporters not originally investigated. - (1) If a product is subject to anti-dumping duties, the designated authority shall carry out a periodical review for the purpose of determining individual margins of dumping for any exporters or producers in the exporting country in question who have not exported the product to India during the period of investigation, provided that these exporters or producers show that they are not related to any of the exporters or producers in the exporting country who are subject to the anti-dumping duties on the product.

(2) The Central Government shall not levy anti-dumping duties under sub-section (1) of section 9A of the Act on imports from such exporters or producers during the period of review as referred to in sub-rule (1) of this rule:

Provided that the Central Government may resort to provisional assessment and may ask a guarantee from the importer if the designated authority so recommends and if such a review results in a determination of dumping in respect of such products or exporters, it may levy duty in such cases retrospectively from the date of the initiation of the review.

¹*[(3) The anti-dumping duty already imposed for co-operative un-sampled exporters or producers may also be extended to such exporters or producers who were not originally investigated.*

^{1a} [Explanation. ***]

17. Article 9.5 of the WTO Agreement states as under –

“9.5 If a product is subject to anti-dumping duties in an importing Member, the authorities shall promptly carry out a review for the purpose of determining individual margins of dumping for any exporters or producers in the exporting country in question who have not exported the product to the importing Member during the period of investigation, provided that these exporters or producers can show that they are not related to any of the exporters or producers in the exporting country who are subject to the anti-dumping duties on the product. Such a review shall be initiated and carried out on an accelerated basis, compared to normal duty assessment and review proceedings in the importing Member. No anti-dumping duties shall be levied on imports from such exporters or producers while the review is being carried out. The authorities may, however, withhold appraisement and/or request guarantees to ensure that, should such a review result in a determination of dumping in respect of such producers or exporters, anti-dumping duties can be levied retroactively to the date of the initiation of the review.”

18. In terms of the aforesaid Rule, the provisions in the WTO Agreement and the past practice of the Authority, a new shipper review investigation is to be carried out under the following circumstances for the purpose of determining individual dumping margin in respect of any exporter or producer from the subject country attracting anti-dumping duty:
 - i. that the exporter or producer has not exported the product under consideration during the period of investigation, and
 - ii. that exporter or producer shows that they are not related to any of the exporter or producer in the exporting country who are subject to the anti-dumping duties on the product concerned.
19. In the instant case M/s Al-Razi Chemical Complex Limited, Bangladesh (Producer/Exporter) has filed an application before the Authority seeking individual dumping margin concerning exports of “Hydrogen Peroxide” and requested for initiation of the new shipper review.
20. As regards the eligibility of the producer/exporter for claiming ‘NSR’, the Authority has conducted detailed examination of the claims made by the producer/exporter including the table study of various documents submitted with respect to data/ information filed by the producer/exporter. Such examinations were conducted in view of the requirements of Rule 22 and the past practices of the Authority. No interested party has provided evidence of non-fulfilment of the condition by the producer/exporter for NSR by way of any substantive evidences other than legal submissions. The Authority, therefore, holds that the producer/exporter is eligible to seek a new shipper review in the instant case.
21. With regard to the contentions on the relevance of the final findings in this matter in view of the expiry of the anti-dumping duties on the subject goods from the subject countries, the Authority notes that the investigation was initiated under Rule 22 while the duties were in force and a final finding is essential to take the investigation to a logical conclusion which shall be essential in particular to determine the actual duty liability for the

provisional assessment period during which the imports from the applicant were made without paying any actual ADD.

22. With regard to the contentions that imports through Petrapole ports are subjected to reassessment, the Authority has determined the individual margin for the applicant based on the verified information on the normal value and the export price submitted in their response.

F. DETERMINATION OF INDIVIDUAL DUMPING MARGIN FOR THE APPLICANT

23. To determine the dumping margin for the applicant, the data/submissions made by the applicant in its application for initiation of the investigation and the data filed subsequently during the course of verification was examined. The following are the observations:

- (i) The applicant in its application dated *** submitted the details of the domestic sales for the period from *** to *** (Annexure-4 of the application). Subsequently, the applicant filed an EQR which contained the domestic sales for the period from *** to *** (Appendix-4A). Both were compared and it is noted that out of *** domestic sales transactions reported in the initial application, only *** transactions matched with the transactions filed in Appendix-4A of EQR. The producer-exporter was requested to provide justification/clarification for this mis-match in domestic sales. In response, the producer-exporter vide email dated *** stated that the sales data filed along with NSR application was not correct as this data was prepared as per the proforma invoices and not as per the commercial invoices. The reply is not acceptable as the application was filed on *** and even the domestic sales transactions undertaken on *** were not matching.
- (ii) Further, the cost data filed in EQR (on ***) has been drastically changed by the producer-exporter in its submissions filed at the time of the verification of data on ***. The Authority had asked for the reasons for this change in the data and in response of justification for the same, the producer-exporter vide email dated *** stated that the App. 7 was prepared from unaudited books of accounts at the time of submission of EQR, while the data at the time of verification was based on the audited accounts in which some expenses were capitalised. The reply is not acceptable as there has been substantial change in the figures of raw material, utilities, packing, etc. which have resulted in turning of loss of BDT *** crore into profit of BDT *** crore. Further, even the previous year figures for the period from *** to *** have been changed and the previous year loss of BDT *** crore has been turned into profit of BDT *** crore.

24. Therefore, the Authority has determined to reject the response filed by /s Al-Razi Chemical Complex Limited, Bangladesh (Producer/Exporter).

G. POST DISCLOSURE COMMENTS

G.1. Submissions by the applicant/producer/exporter:

25. The mismatch in the data has been on account of delay in finalisation of accounts and some human errors in reporting due to lack of understanding of the technical requirements to be observed while reporting the data at the end of the company officials which could only be noticed eventually and these admitted errors, should not please lead to the rejection of the response itself filed by the applicant as proposed.
26. With regard to the first issue of mismatch in sales data, the reporting of sales was done at the time of application, regrettably, based on proforma invoices as eventually realised and since the official undertook the reporting quit the job thereafter, this inconsistency could not be immediately noticed and the applicant ended up in reporting incorrect numbers which was not as per commercial invoices. It may be noted that the Company had no intention of any wrong reporting and the inconsistency has been only a human error.
27. However, the correct verifiable sales data has been availed to the Authority prior to the verification and it is respectfully prayed that the Authority may kindly adopt the rectified data now and determine margins for the applicant instead of rejecting the entire response. The mismatch in data did not lead to any incorrect determination of margin in this matter so far and condoning such a human error shall only be in the interest of justice and fair play.
28. With regard to the second observation that the cost data filed in EQR has been drastically changed by the producer-exporter in its submissions filed at the time of the verification of data including previous year, it is respectfully submitted that the regrettable inconsistency in the costing data has been the result of delay in audit process and some substantial changes in treatment of cost items occurred as part of the audit process. The audit was delayed due to covid restrictions and this was the reason for delay in audit for the previous year also. The Authority pertinently noted such delay in the previous year also. However, it may be noted that in view of such difficulties, the National Revenue Board of Bangladesh extended the time limits for Filing of Income Tax Return for Assessment Year 2021-2022 for Company till 15th June, 2022.
29. The relevant notification along with translation of relevant portion is provided to the Authority. The Authority may also note that the Company has commenced commercial production in the recent times and the change in treatment of certain cost items etc. needs to be seen in this context as the process was evolving and dynamic.

30. The final cost data based on audited records submitted prior to the verification is completely reliable and authentic and it is our respectful prayer that even on this inconsistency pointed out, the Authority may note that the inconsistency was inadvertent and occurred only for the reason of changes in treatment of cost and the applicant never resorted to providing any incorrect data leading to incorrect determinations by the Authority.
31. Opportunity to rectify the errors in data is very much part of the investigation process before the Authority and it may kindly be treated that the applicant rectified certain mismatches in the data on its own prior to the verification. The Authority has final and verifiable audited information for the purpose of final finding in this matter and rejection of response may please be avoided in such a scenario.

G.2. Submissions by the domestic industry/other interested parties:

32. The domestic sales data and cost of production data have undergone very material change between the time of filing of application and at the time of verification. It is also very evident from the disclosure statement that whereas the applicant had first reported that he suffered financial losses, it has now reported that it has earned profit.

G.3 Examination by the Authority

33. The Authority notes that the applicant has accepted the mismatch in the data and admitted the error but has said that the mismatch was on account of delay in finalisation of accounts and some human errors in reporting due to lack of understanding of the technical requirements to be observed while reporting the data at the end of the company officials. The applicant has further stated that the reporting of sales was done at the time of application, regrettably, based on proforma invoices as eventually realised and since the official undertook the reporting quit the job thereafter, this inconsistency could not be immediately noticed and the applicant ended up in reporting incorrect numbers which was not as per commercial invoices. However, the correct verifiable sales data has been made available to the Authority prior to the verification. With regard to the observation that the cost data filed in EQR has been drastically changed by the producer-exporter in its submissions filed at the time of the verification of data including previous year, the applicant has submitted that the regrettable inconsistency in the costing data has been the result of delay in audit process and some substantial changes in treatment of cost items occurred as part of the audit process. The audit was delayed due to covid restrictions and this was the reason for delay in audit for the previous year also. The Authority is of the opinion that the explanation of the applicant that error occurred in reporting the data due to human error and lack of understanding of the technical requirements to be observed while reporting the data at the end of the company officials is not a sound reasoning and thus unacceptable. Also, the Authority is of the opinion that the explanation of the applicant that the regrettable inconsistency in the costing data filed in the EQR has been the result of delay in audit process and some substantial changes in treatment of cost items occurring as part of the audit process is also not a plausible and sound reasoning. The Authority thus does not accept the explanation of the applicant. Therefore, the Authority has decided to reject the response filed by M/s Al-Razi Chemical Complex Limited, Bangladesh (Producer/Exporter).

H. CONCLUSION AND RECOMMENDATION

34. After examining the submissions made by M/s Al-Razi Chemical Complex Limited, Bangladesh (Producer/Exporter) and the domestic industry and considering the facts available on record, the Authority concludes that the explanation of the applicant that the error in reporting the data occurred due to human error and lack of understanding of the technical requirements to be observed while reporting the data at the end of the company officials and that regrettable inconsistency in the costing data filed in the EQR has been the result of delay in audit process and some substantial changes in treatment of cost items occurring as part of the audit process not a plausible and sound explanation. The Authority thus decides to reject the response filed by M/s Al-Razi Chemical Complex Limited, Bangladesh and recommends not to grant individual duty to M/s Al-Razi Chemical Complex Limited, Bangladesh.

I. FURTHER PROCEDURE

35. Landed value of imports for the purpose of this notification shall be the assessable value as determined by the Customs under the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and includes all duties of customs except duties under sections 3, 3A, 8B, 9 and 9A of the said Act.
36. An appeal against the order of the Central Government arising out of this finding shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act.

ANANT SWARUP, Designated Authority